जीवन में हमेशा एकदूसरे को समझने का प्रयत्न करिए, परखने का नहीं।
– अज्ञात

अभियान जोर–शोर से शुरू

जम्मू–कश्मीर का विशेष दर्जा खत्म हुए छह महीने होने को आ रहे हैं। इतने समय बाद जन संपर्क अभियान चलाने का कुछ फौरी मकसद भी जरूर होना चाहिए। जम्मू–कश्मीर में लगभग साढ़े बारह हजार पंचायतों के चुनाव फरवरी में कराए जाने की बात है।

नवीन जोशी।

केंद्र सरकार ने जम्मू–कश्मीर के लोगों तक पहुंचने का अभियान जोर–शोर से शुरू कर दिया है। केंद्रीय मंत्रिमंडल के एक–दो नहीं, पूरे 36 मंत्री बीते शनिवार से इस अभियान में जुट गए हैं, जो 24 जनवरी तक चलना है। पिछले साल 5 अगस्त को संविधान के अनुच्छेद 370 से जुड़ी विशेष व्यवस्था खत्म किए जाने के बाद सरकार की ओर से वहां के लोगों तक पहुंचने की यह पहली बड़ी पहल है। अनुच्छेद 370 का खात्मा सचमुच एक ऐसा ऐतिहासिक कदम था जिसने इस क्षेत्र में रहने वाले हर व्यक्ति को राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक और मनोवैज्ञानिक रूप से प्रभावित किया।

ऐसे में सरकार लोगों तक पहुंचने का विशेष प्रयत्न कर रही है तो इसके पीछे उद्देश्य चाहे जो भी हो, इसके महत्व को कम करके नहीं देखा जा सकता। हालांकि लोगों के दिलो–दिमाग तक पहुंचने और उन्हें अपनी स्थिति बताने के लिहाज से थोड़ी देर जरूर हो गई है। यह अभियान अगर पहले शुरू किया गया होता तो न सिर्फ राज्य के नागरिकों के लिए बल्कि देश के लिए भी यह ज्यादा फायदेमंद होता। जम्मू–कश्मीर का विशेष दर्जा खत्म हुए छह महीने होने को आ रहे हैं। इतने समय बाद जन संपर्क अभियान चलाने का कुछ फौरी मकसद भी जरूर होना चाहिए। जम्मू–कश्मीर में लगभग साढ़े बारह हजार पंचायतों के चुनाव फरवरी में कराए जाने की बात है। स्वाभाविक है कि इस अभियान को उनसे जोड़ कर देखा जाएगा।

बहरहाल, जनसंपर्क अभियान का चुनावों से सीधा संबंध हो या न हो, इस बात की अनदेखी नहीं की जा सकती कि फिलहाल जम्मू–कश्मीर के दोनों बड़े क्षेत्रीय दलों– नैशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी– का शीर्ष नेतृत्व नजरबंद है। ऐसे में अगर चुनाव होते हैं तो कहा यही जाएगा कि सभी दलों को बराबर का मौका नहीं मिला। बेहतर होगा, सरकार यह सुनिश्चित करे कि जब भी चुनाव हों, वे न केवल निष्पक्ष हों बल्कि उनकी निष्पक्षता में किसी तरह के संदेह की गुंजाइश न रहे। यह खास तौर पर जरूरी इसलिए हो जाता है क्योंकि कुछ पड़ोसी देश इस कोशिश में लगे हैं कि किसी भी बहाने से कश्मीर को लेकर कोई विवाद खड़ा हो जाए, जिसे आधार बनाकर इस मसले को अंतरराष्ट्रीय मंचों पर उठाया जा सके। भारत सरकार बार–बार दोहराती रही है कि कश्मीर हमारा आंतरिक मामला है, लेकिन इसके समानांतर यह ध्यान रखना भी जरूरी है कि हमारी किसी असावधानी से कश्मीर मुद्दे के अंतरराष्ट्रीयकरण की कोशिश में लगी शक्तियों का काम आसान न हो जाए। इस संदर्भ में हमें यह भी समझना होगा कि जब तक कश्मीर के तमाम बड़े नेता नजरबंद हैं और वहां के नागरिकों की सामान्य जिंदगी पर कई तरह की बंदिशें लगी हुई हैं, तब तक जम्मू–कश्मीर में स्थिति सामान्य होने का दावा पूरी तरह विश्वसनीय नहीं माना जाएगा।

कुछ समय पहले इंटरनेट सेवा बहाल करने से जुड़े फैसले में ऐसा एक इशारा सुप्रीम कोर्ट की ओर से आ चुका है, लिहाजा जनसंपर्क जितनी ही सक्रियता सरकार को इन पहलुओं पर भी दिखानी चाहिए।

अजीब स्थिति

डॉ. अर्चिका दीदी।

धर्म-दर्शन

हम सभी ने अपने जीवन को खुद ही अजीब स्थिति में लाकर खड़ा कर लिया है और दोषारोपण दूसरों पर। सर्वप्रथम उस ऊर्जा की बात कर लेते है जिसके बिना हमारा जीवन सम्भव नहीं है ,इस ऊर्जा को हम काम ऊर्जा के नाम से जानते है लेकिन इस ऊर्जा की हमारे जीवन में अतिविशिष्ट भूमिका के बावजूद जागरूकता नगण्य स्तर पर है ,इस कारण मनुष्य जीवन में इस ऊर्जा का सर्वाधिक दुरुपयोग किया जा रहा है । हमारे निजी जीवन में भी परिवेश से सम्बन्धित लोगों ने हमें इस से रूबरू नहीं कराया ! इसलिए यह विषय मेरे लिए महत्वपूर्ण है और इसको समझने की जिज्ञासा भी । समस्त प्राणिजगत बिना इस ऊर्जा के सम्भव नहीं ।

संपादकीय

नड्डा ही नए राष्ट्रीय अध्यक्ष

इस हफ्ते बीजेपी को नया राष्ट्रीय अध्यक्ष मिल जाएगा। माना जा रहा है कि बीजेपी के मौजूदा कार्यकारी अध्यक्ष जेपी नड्डा ही पार्टी के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष होंगे। बीजेपी के राष्ट्रीय चुनाव अधिकारी ने पार्टी के नियमों के मुताबिक नामांकन की तारीख का ऐलान भी कर दिया है। राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव के लिए 20 जनवरी को सुबह 10 बजे से 12.30 बजे तक नामांकन होगा, जबकि नाम वापसी का वक्त 1.30 बजे से 2.30 बजे तक का रखा गया है। अगर एक से ज्यादा नामांकन होते हैं और चुनाव की नौबत आती है तो 21 जनवरी को मतदान की तारीख तय की गई है, हालांकि इसकी संभावना नहीं है। यानी 20 जनवरी को ही बीजेपी जेपी नड्डा के नाम का ऐलान पार्टी के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पर कर सकती है। वैसे तो करीब सात महीनों से नड्डा बीजेपी के कार्यकारी अध्यक्ष की जिम्मेदारी संभाले हुए हैं, लेकिन वह कभी इसके मौजूदा अध्यक्ष अमित शाह की छाया से बाहर नहीं निकल पाए। अध्यक्ष बनने के बाद नड्डा को मोदी–शाह की छाया से बाहर निकलना होगा। उसके बाद ही वह दमदार अध्यक्ष के तौर पर देखे जाएंगे। अमित शाह ने मोदी सरकार में गृह मंत्री का पद संभाला तो उसके बाद नड्डा को कार्यकारी अध्यक्ष बनाया गया। लेकिन पार्टी के सभी फैसलों पर अमित शाह की ही छाप दिखी।

अमित शाह ने बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का पद संभालने के बाद पार्टी को जिस मुकाम पर पहुंचाया, नड्डा की तुलना उससे होगी ही। अमित शाह के कार्यकाल में बीजेपी ने यूपी जैसे बड़े राज्य में जीत हासिल की, जहां माना जा रहा था कि जाति समीकरणों के हिसाब से बीजेपी की राह आसान नहीं है। लोकसभा चुनाव में भी बीजेपी ने फिर से धमाकेदार वापसी की। पार्टी कार्यकर्ताओं के बीच अमित शाह की इमेज एक सख्त नेता की है।

इस मामले में आंतरिक उपद्रव से ग्रस्त केन्या और इजिप्ट जैसे देशों को भी हमसे ऊंची जगह मिली है। हालांकि, इस मामले में भी पिछले साल से हमारे हालात थोड़े सुधरे हैं।

दुनिया की राय हमारे बारे में

भावना शर्मा।

यह सोचकर थोड़ा संतोष किया जा सकता है कि दुनियाभर में रहने लायक सबसे अच्छे मुल्कों की सूची में हमारी स्थिति थोड़ी सुधरी है लेकिन महिलाओं की हैसियत और बच्चों के लालन–पालन के मामले में दुनिया की राय हमारे बारे में आज भी बेहतर नहीं है। यूएस न्यूज, वर्ल्ड रिपोर्ट और वॉर्टन स्कूल द्वारा कराए गए सर्वेक्षण के अनुसार, दुनिया में रहने लायक 73 देशों की सूची में भारत 25वें स्थान पर है जबकि पिछले साल हमें 27वीं रैंक मिली थी। यह रैंकिंग विभिन्न देशों को लेकर विश्वस्तर पर बनी धारणा के आधार पर की जाती है। व्यापार, निवेश, पर्यटन के अनुकूल माहौल और सामाजिक स्थिति जैसी कसौटियों पर लोगों की राय को परखा जाता है।

अब जैसे बच्चों के लालन–पालन की दृष्टि से सबसे अच्छे देशों की लिस्ट में भारत को 59वां स्थान दिया गया है। इस मामले में आंतरिक उपद्रव से ग्रस्त केन्या और इजिप्ट जैसे देशों को भी हमसे ऊंची जगह मिली है। हालांकि, इस मामले में भी पिछले साल से हमारे हालात थोड़े सुधरे हैं। 2019 में हमारा स्थान इस खाने में 65वां था। महिलाओं के लिए सर्वश्रेष्ठ देशों की सूची में हमारा मुकाम 58वां है और इस मामले

में हम पिछले साल के मुकाबले एक पायदान नीचे फिसले हैं। यूएई, कतर और सऊदी अरब जैसे कम स्त्री स्वतंत्रता वाले देशों का यह पहलू हमसे बेहतर है। इन देशों का रूढ़िवादी प्रशासन औरतों को भारत जितने अधिकार नहीं देता लेकिन मामले का एक पहलू यह भी है कि भारत में महिलाओं के खिलाफ हो रहे अपराध विश्वभर में चर्चा का विषय बनते हैं जबकि इन देशों में इस पक्ष पर ज्यादा बात ही नहीं होती है।

2018 में थॉमसन रॉयटर्स फाउंडेशन की ओर से जारी एक सर्वे में भारत को पूरी दुनिया में महिलाओं के लिए सबसे खतरनाक और असुरक्षित देश बताया गया था। जाहिर है, यह राय महिलाओं के खिलाफ यौन हिंसा, मानव तस्करी और यौन व्यापार में धकेले जाने की खबरों के आधार पर ही बनी थी। इसके जल्दी बदलने का कोई कारण नहीं है क्योंकि हर दो–चार महीने पर ऐसा कोई न कोई बड़ा हादसा सामने आ ही जाता है। महिला सुरक्षा को लेकर बातें जरूर बड़ी–बड़ी होती हैं लेकिन जमीन पर कुछ खास बदलता नजर नहीं आता है।

भारत में बच्चों की स्थिति को लेकर भी जो राय बनी है, उसकी एक बड़ी वजह हाल के दिनों में कुछेक महानगरीय स्कूलों में बच्चों के साथ हुए हादसे ही हैं। यह सही है कि विकास के क्रम में भारत के शहरों में रहन–सहन के स्तर पर सुविधाएं बढ़ी हैं और माहौल बिजनस फ्रेंडली हुआ है लेकिन सक्षम कानून–व्यवस्था, संवेदनशील और सहिष्णु समाज का लक्ष्य अभी हमारे अजेंडा पर ही नहीं है। इसे हासिल करने के बाद ही हम हर किसी के रहने लायक देश कहला सकेंगे।

सूडोकु नवताल- 5225

सरल

5		9		8	3	2		
	2		4					8
3	8		5	2	6	1		
	7						9	5
9		3	6		8	7		4
2	6						1	
		5	2	7	1		8	6
6					4		7	
		8	9	6		4		2

Jagrutidaur.com, Bangalore

- प्रत्येक पंक्ति में 1 से 9 तक के अंक भरे जाने आवश्यक हैं.
- प्रत्येक आड़ी और खड़ी पंक्ति में एवं 3×3 के वर्ग में किसी भी अंक की पुनरावृत्ति न हो इसका विशेष ध्यान रखें.
- पहले से मौजूद अंकों को आप हटा नहीं सकते.
- पहेली का केवल एक ही हल है.

सूडोकु नवताल -5224 का हल

8	2	5	3	6	7	9	1	4
4	6	1	8	9	2	3	7	5
3	7	9	1	5	4	6	8	2
1	3	7	4	2	9	5	6	8
6	5	2	7	1	8	4	9	3
9	8	4	6	3	5	1	2	7
2	4	6	9	8	3	7	5	1
5	1	3	2	7	6	8	4	9
7	9	8	5	4	1	2	3	6

अपना ब्लॉग

दिल्ली से दक्षिण तक की चुनौती

मुकुल श्रीवास्तव। नड्डा ऐसे वक्त में राष्ट्रीय अध्यक्ष का पद संभालने जा रहे हैं जब दिल्ली में विधानसभा चुनाव हैं। दिल्ली में बीजेपी लंबे वक्त से सत्ता से बाहर है और पिछले विधानसभा चुनाव में 70 में से महज तीन सीटें ही जीतने में सफल रही, जबकि इसके कुछ ही पहले हुए लोकसभा चुनाव में पार्टी ने दिल्ली की सातों लोकसभा सीटें जीती थी। इस बार भी दिल्ली से सातों सांसद बीजेपी के ही हैं। दिल्ली बीजेपी में नेताओं की आपसी खींचतान जगजाहिर है। पार्टी शायद यहां किसी सीएम कैंडिडेट का ऐलान नहीं करेगी। ऐसे में बीजेपी पीएम मोदी के नाम पर दिल्ली चुनाव लड़ेगी। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के नाते नड्डा की साख भी इसमें दांव पर लगी रहेगी। इसी साल के अंत में बिहार में भी विधानसभा चुनाव है। बीजेपी कह चुकी है कि बिहार विधानसभा चुनाव नीतीश कुमार की अगुवाई में लड़ेंगे। 2021 में पश्चिम बंगाल का चुनाव तो एक तरह से अग्नि परीक्षा ही रहेगा।